

मध्य प्रदेश विधानसभा द्वारा समान नागरिक संहिता (युनिफॉर्म सिविल कोड) विधेयक, 2026 का पारित होना केवल एक विधायी प्रक्रिया नहीं, बल्कि समान न्याय और समान नागरिक अधिकारों की दिशा में उठाया गया एक महत्वपूर्ण कदम है. उत्तराखंड, असम और गोवा के बाद मध्य प्रदेश इस दिशा में आगे बढ़ने वाला देश का चौथा राज्य बन गया है. यह निर्णय लंबे समय से चल रही उस संवैधानिक सोच को आगे बढ़ाता है, जिसका उद्देश्य सभी नागरिकों के लिए समान नागरिक कानून की व्यवस्था सुनिश्चित करना है. भारतीय संविधान के नीति-निर्देशक तत्वों में अनुच्छेद 44 स्पष्ट रूप से राज्य को पूरे देश में समान नागरिक संहिता लागू करने का प्रयास करने का निर्देश देता है. यद्यपि नीति-निर्देशक तत्व न्यायालय में प्रवर्तनीय नहीं हैं, लेकिन वे शासन की दिशा और लोकतांत्रिक मूल्यों के मार्गदर्शक सिद्धांत हैं.

एक लाख से दो लाख



जब 2020 में कोविड-19 महामारी ने लोगों के जीवन और आजीविका पर बुरा असर डाला, तो माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने महसूस किया कि फिर से पूर्वस्थिति बहाल करने की प्रक्रिया केवल बड़े उद्योगों तक सीमित नहीं रहनी चाहिए. इसे सबसे छोटे उत्पादकों और उद्यमों तक भी पहुँचाना चाहिए, खासकर उन उद्यमों तक, जो भारत के गांवों और छोटे शहरों में कार्यरत हैं. इस उद्देश्य के साथ, उस साल, आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यम औपचारिकीकरण योजना शुरु की गई थी.

इसकी शुरुआत खाद्य अर्थव्यवस्था के उस हिस्से के साथ हुई, जो लंबे समय तक औपचारिक वित्त और संस्थागत समर्थन से बाहर रहा था-सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण, जो पहले ही उत्पादन व बिक्री कर रहे थे और कुछ लोगों को रोजगार दे रहे थे, लेकिन जिनके पास आगे बढ़ने के लिए आवश्यक पूंजी या मार्गदर्शन नहीं था. यह योजना उस विश्वास को प्रतिबिंबित करती है, जिसे प्रधानमंत्री लगातार मानते रहे हैं, कि भारत की वृद्धि इसके आधार से शुरू होनी चाहिए, यानि उन लोगों के बीच, जो अपने खुद के



किसी भी राज्य की आर्थिक प्रगति का सबसे विश्वसनीय पैमाना केवल विकास दर नहीं, बल्कि निवेशकों का उस राज्य की नीतियों, प्रशासन और भविष्य पर विश्वास होता है। उद्योग वहीं स्थापित होते हैं, जहां नीति में स्थिरता, प्रशासन में पारदर्शिता, आधारभूत संरचना में मजबूती और शासन में निर्णय लेने की क्षमता हो. पिछले कुछ वर्षों में मध्यप्रदेश ने इन सभी क्षेत्रों में उल्लेखनीय सुधार करते हुए स्वयं को देश के उभरते औद्योगिक केंद्रों में स्थापित करने की दिशा में सार्थक प्रयास किए हैं.

नई दिल्ली में आयोजित भारत टेक्स-2026' तथा इंटरैक्टिव सेशन 'अन इंवेस्टमेंट ऑपॉर्च्युनिटीज इन मध्यप्रदेश' के दौरान प्रदेश को 20 हजार 193 करोड़ रुपये के निवेश प्रस्ताव प्राप्त होना इसी बदलते विश्वास का

संपादकीय बोर्ड | प्रबंध संपादक : सुमीत माहेश्वरी, समूह संपादक : क्रांति चतुर्दशी

शब्द-सागर : डॉ. सागर खादीवाला

CROSS WORD12326

डॉ. सागर खादीवाला

1	2	3	4	5
6			7	
8		9		10
		11		12
	13			14
16		17		18
19		20		21
22			23	

बाएं से दाएं

1. बहुत बड़ा, महत्तर, महान, भारत के मुगल राजवंश का तीसरा बादशाह (उर्दू) 4. अन्न 6. स्पष्ट पर मंद स्वर में किया जाने वाला उच्चारण (सं.) 7. समझ, बुद्धि 8. एक वृक्ष या उसका लंबा गुदेदार फल, कदली 9. हीन, ओछा, नीच 10. दूसरा, और, भिन्न 11. कामदेव, एक प्रसिद्ध आयुर्वेद का रस, लौंग,... अहिराण्य का एक द्वारपाल 13. वह रचना जो छोड़ोबड़ न हो 14. दूध पीता बच्चा (सं.) 16. सिलाई करना 18. बीस वस्तुओं का समूह, कोड़ी 19. पदार्थ का वह गुण जिसका ज्ञान केवल अंशों द्वारा ही होता है 20. वैमनस, मनमुटाव 22. दारचीनी जाति का एक सदाबहार वृक्ष जिसके पत्ते तेजपान कहलाते हैं 23. धोखा देकर माल लूटना, छल करना

ऊपर से नीचे

Solution 12325

छ	प	न	म	ह	मा	न
नी	र	श	ह	र	दा	र
व	जी	क	र	जा	सि	हि
या	रि	त	जा	श	ह	
क	श	जा	न	व	र	
मा	ना	ती	ध	मा	अ	
सा	भ	दा	य	क	ना	ली
व	न	दा	नि	व		

यूसीसी : समान न्याय की दिशा में ऐतिहासिक कदम

संविधान निर्माताओं की यह मंशा थी कि समय के साथ देश ऐसी व्यवस्था की ओर बढ़े, जहां नागरिकों के व्यक्तिगत अधिकार धर्म के आधार पर अलग-अलग न होकर समान संवैधानिक सिद्धांतों पर आधारित हों. मध्य प्रदेश के यूसीसी विधेयक में कई ऐसे प्रावधान शामिल किए गए हैं, जो सामाजिक न्याय और पारदर्शिता को मजबूत करते हैं. बहुविवाह, तीन तलाक और निवृत्त हलाला जैसी प्रथाओं पर रोक, विवाह और तलाक का अनिवार्य पंजीकरण, लिव-इन रिलेशनशिप का पंजीकरण तथा महिलाओं और बच्चों को उत्तराधिकार एवं गोद लेने के मामलों में समान अधिकार देना समाज में समानता की भावना को सुदृढ़ करेगा. साथ ही, अनुसूचित जनजातियों को इस कानून के

दायरे से बाहर रखकर उनकी परंपराओं और सांस्कृतिक पहचान का सम्मान भी किया गया है, जो संवैधानिक भावना के अनुरूप है. निस्संदेह, यूसीसी जैसे विषय पर अलग-अलग मत हो सकते हैं. लोकतंत्र में असहमति का सम्मान होना चाहिए और कानून के विभिन्न पहलुओं पर रचनात्मक चर्चा भी आवश्यक है. यदि किसी प्रावधान को लेकर व्यावहारिक या कानूनी चिंताएं हैं, तो उन्हें संवैधानिक और लोकतांत्रिक मंचों पर रखा जाना चाहिए. लेकिन इस विषय को केवल वोट बैंक की राजनीति का माध्यम बनाना न तो समाज के हित में है और न ही संविधान की भावना के अनुरूप. देश को यह समझना होगा कि समान नागरिक संहिता का मूल उद्देश्य किसी धर्म विशेष को लक्ष्य बनाना नहीं, बल्कि

सभी नागरिकों के लिए समान अधिकार और समान दायित्व सुनिश्चित करना है. यदि महिलाओं, बच्चों और परिवार संस्था को अधिक कानूनी सुरक्षा मिलती है तथा नागरिक अधिकारों में समानता आती है, तो इसे सामाजिक सुधार की दिशा में सकारात्मक पहल के रूप में देखा जाना चाहिए. प्रदेश का यह निर्णय आने वाले समय में राष्ट्रीय विमर्श को नई दिशा देगा.

अब आवश्यकता इस बात की है कि इस कानून के क्रियान्वयन में पारदर्शिता, संवेदनशीलता और व्यापक जनजागरूकता सुनिश्चित की जाए. साथ ही, सभी पक्षों को राजनीतिक आरोप-प्रत्यारोप से ऊपर उठकर संविधान की मूल भावना, समानता, न्याय और नागरिक अधिकारों,को केंद्र में रखकर विचार करना चाहिए. यही लोकतंत्र की परिपक्वता और भारत की संवैधानिक प्रतिबद्धता का वास्तविक परिचायक होगा.

28 के चुनावों की दशा और दिशा निर्धारित करेगा दतिया का जनादेश



हरीश दुबे

दतिया में चुनावी बिसात पर मुकाबला कॉटे का फंस गया है. सत्तारूढ़ दल के लिए तो यह प्रतिष्ठा की लड़ाई बन ही गई है. कांग्रेस भी पंद्रह साल के लंबे अंतराल के बाद पिछले चुनाव में कब्जे में आई इस सीट



कांग्रेस ने बड़ी मशक्कत कर अवधेश नायक को तो भाजपा में जाने से रोक लिया है और वे कांग्रेस के समर्थन में सभाएं एवं बैठकें लेने लगे हैं लेकिन निवर्तमान विधायक राजेन्द्र भारती अभी भी कांग्रेस के समर्थन में पूरी तरह सक्रिय नहीं हुए हैं, इसकी एक वजह उनकी अस्वस्थता भी बताई जा रही है, कांग्रेस राजेंद्र भारती की धर्मपत्नी या बेटे को टिकट देने के लिए तैयार थी लेकिन राजेंद्र भारती ने खुद ही बयान जारी कर अपने परिवार के किसी सदस्य के चुनाव लड़ने से इंकार कर दिया था. यह कह सकते हैं कि पीतांबर नगरी से आने वाला जनादेश 2028 के चुनाव समर की दशा और दिशा निर्धारित करेगा.

चेंबर चुनाव के नतीजों ने दरका दीं हाउसों की दीवारें

26 के चेंबर चुनाव के नतीजे ने इस सवासौ साल पुरानी मध्यभारत की सबसे बड़ी व्यापारिक संस्था के इतिहास में नया ही इतिहास लिख दिया है. करीब कर दशक तक चेंबर के मुखिया बने स्व. बाबू दुर्गाप्रसाद मंडेलिया द्वारा खुद ही पद छोड़ने के बाद से चेंबर पूरी तरह दो हाउसों में बंट गया था. हाउस ही अपने पैनल चुनाव मैदान में उतारते थे और स्वतंत्र प्रत्याशियों के मुखिया ही नहीं था. इस बार के चेंबर चुनाव में ग्लैमर और साधन सम्पन्नता से दूर जमीनी स्तर पर सक्रिय रहने वाले डॉ. प्रवीण अग्रवाल ने व्हाइट हाउस को कड़ी चुनौती देते हुए उसके कड़ाकर प्रत्याशी पारस जैन को छहसी से ज्यादा वोटों के बड़े अंतर से शिकस्त देकर चेंबर का परिदृश्य ही बदल दिया. यह भी पहली मर्तबा हुआ जब किसी अध्यक्ष को दोबारा से चुना गया.

फिर गुटबाजी की भेंट चढ़ी एल्डरमैनों की लिस्ट

सत्तारूढ़ दल में स्थानीय स्तर पर व्याप्त खेमेबाजी और गुटिय असंतुलन की स्थिति अब ग्वालियर का ही नुकसान करने लगी है. छप्पों की गुटिय राजनीति के चलते पहले मेला, साड़ा और जीडीए के अध्यक्ष और ग्वाथ्यक्ष पदों पर नियुक्तियां बरसों तक अटक रहीं और मौजूदा सरकार का आधा कार्यकाल गुजर जाने के बाद ग्वालियर के ये तीन प्राधिकरण किसी तरह भरे जा सके. अब यही कहानी फिर दोहराई जा रही है. प्रदेश सरकार ने स्थानीय निकायों में राजनीतिक नियुक्तियों का सिलसिला शुरू करते हुए बाकी 13 नगर निगमों में तो एल्डरमैन नियुक्त कर दिए लेकिन इस सूची में ग्वालियर नगर निगम को वॉटिंग में रखा गया है जबकि मौजूदा ग्वालियर निगम परिषद का कार्यकाल खस होने में एक साल से भी कम समय बचा है, तो क्या ग्वालियर निगम में चंद महीनों के लिए एल्डरमैन बनाए जाएंगे, या फिर नियुक्त होंगे ही नहीं. ग्वालियर में भाजपा स्पष्ट तौर पर सिधिया और नरेंद्र सिंह के खेमों में बंटी है, दोनों खेमों को एक दूसरे के द्वारा अनुशासित नाम किसी भी सूत्रत में नहीं सुनाते हैं. यही वजह है कि ग्वालियर निगम के एल्डरमैनों की लिस्ट कई बार बनाई और डस्टबिन में डाली जा चुकी है. ग्वालियर में सत्तादल के दो बड़े तबोतों और विभिन्न गुटों के बीच संतुलन बनाना सरकार के लिए चुनौती बना है. यही कारण है कि यहां एल्डरमैन की नियुक्ति एक बार फिर से टाल दी गई है.

निवेश के नए विश्वास का केंद्र बनता मध्यप्रदेश

संकेत है. इन प्रस्तावों से लगभग 27 हजार 600 प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रोजगार सृजित होने की संभावना व्यक्त की गई है. यह केवल निवेश का आंकड़ा नहीं, बल्कि मध्यप्रदेश की औद्योगिक नीतियों के प्रति बढ़ते विश्वास का संकेतक भी है. मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने निवेशकों के समक्ष प्रदेश की औद्योगिक संभावनाओं को जिस स्पष्टता और आमनिश्चवास के साथ प्रस्तुत किया, उससे यह संदेश गया कि मध्यप्रदेश अब केवल संसाधन सम्पन्न राज्य नहीं, बल्कि निवेश के लिए तैयार राज्य भी है. पर्याप्त भूमि बैंक, अपेक्षाकृत शांत औद्योगिक वातावरण, निम्बों विद्युत आपूर्ति, बेहतर सड़क एवं रेल संपर्क, विकसित हो रहा लॉजिस्टिक्स नेटवर्क और उद्योग समर्थक नीतियाँ प्रदेश की प्रमुख शक्तियों के रूप में उभर रही हैं.

मध्यप्रदेश की सबसे बड़ी विशेषता उसकी

अंततः निवेश केवल पूंजी का प्रवाह नहीं होता; वह विश्वास, स्थिरता और भविष्य की संभावनाओं का संकेत भी होता है. मध्यप्रदेश ने इस दिशा में एक सकारात्मक शुरुआत की है. अब आवश्यकता इस बात की है कि यह विश्वास उद्योगों, रोजगार और समावेशी विकास में परिवर्तित हो. यही किसी भी निवेश नीति की वास्तविक सफलता और किसी भी सरकार की सबसे बड़ी उपलब्धि होगी.

भौगोलिक स्थिति है. देश के मध्य में स्थित होने के कारण यह उत्तर और दक्षिण तथा पूर्व और पश्चिम भारत के बीच एक स्वाभाविक औद्योगिक और लॉजिस्टिक केंद्र बनने की क्षमता रखता है. यदि इस भौगोलिक लाभ का योजनाबद्ध उपयोग किया जाए, तो प्रदेश विनिर्माण और वितरण—दोनों क्षेत्रों में राष्ट्रीय स्तर पर महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है. टेक्सटाइल क्षेत्र में प्रदेश की संभावनाएँ विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं. कपास उत्पादन में अग्रणी होने के साथ-साथ धार में विकसित हो

रहा पीएम मित्रा पार्क वस्त्र उद्योग के लिए नई संभावनाएँ लेकर आया है. भारत टेक्स-2026 में प्राप्त निवेश प्रस्ताव यह संकेत देते हैं कि उद्योग जगत अब मध्यप्रदेश को केवल कच्चे माल के उत्पादक राज्य के रूप में नहीं, बल्कि मूल्य संवर्धन और निर्यात आधारित उत्पादन के केंद्र के रूप में भी देखने लगा है. इसी प्रकार रक्षा उत्पादन, डेटा सेंटर, इलेक्ट्रॉनिक्स, नवीकरणीय ऊर्जा, खाद्य प्रसंस्करण और पर्यटन जैसे क्षेत्रों में निवेश की संभावनाएँ प्रदेश की अर्थव्यवस्था को बहुआयामी स्वरूप देने

की दिशा में महत्वपूर्ण कदम हैं. इससे न केवल औद्योगिक आधार विस्तृत होगा, बल्कि रोजगार के नए अवसर भी सृजित होंगे. हालाँकि, निवेश सम्मेलनों की वास्तविक सफलता केवल हस्ताक्षरित एमओयू की संख्या से नहीं आंकी जाती. उनकी सफलता का वास्तविक मापदंड यह होता है कि उनमें से कितनी परियोजनाएँ समयबद्ध रूप से धरातल पर उतरती हैं और स्थानीय अर्थव्यवस्था को किनारा लाभ पहुँचाती हैं. इस दृष्टि से राज्य सरकार का यह दावा महत्वपूर्ण है कि पूर्व में प्राप्त अनेक निवेश प्रस्ताव अब क्रियान्वयन के चरण में पहुँच चुके हैं. यदि यह गति निरंतर बनी रहती है, तो निवेशकों का विश्वास और अधिक सुदृढ़ होगा. आज वैश्विक निवेश की प्रतिस्पर्धा में प्रत्येक राज्य स्वयं को अधिक आकर्षक बनाने का प्रयास कर रहा है. ऐसे समय में मध्यप्रदेश के सामने अवसर भी है और चुनौती भी. अवसर इसलिए कि उसके पास संसाधन,

भूमि, श्रमशक्ति और भौगोलिक अनुकूलता है; चुनौती इसलिए कि निवेशकों की अपेक्षाएँ अब केवल घोषणाओं से पूरी नहीं होतीं, बल्कि समयबद्ध अनुमतियों, गुणवत्तापूर्ण अधोसंरचना और सुगम प्रशासन से पूरी होती हैं. जनवरी 2027 में प्रस्तावित ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट इसी दिशा में अगली महत्वपूर्ण परीक्षा होगी. यह केवल निवेश आकर्षित करने का मंच नहीं, बल्कि यह बताने का अवसर भी होगा कि मध्यप्रदेश अपने निवेश वादों को किस सीमा तक उद्योगों और रोजगार में परिवर्तित कर पाया है.

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा विकसित भारत-2047 का जो लक्ष्य निर्धारित किया गया है, उसकी सफलता राज्यों की आर्थिक क्षमता और औद्योगिक प्रगति पर भी निर्भर करेगी. मध्यप्रदेश यदि अपनी वर्तमान गति, नीतिगत निरंतरता और प्रशासनिक दक्षता को बनाए रखता है, तो वह विकसित भारत की यात्रा में महत्वपूर्ण योगदान देने वाले अग्रणी राज्यों में शामिल हो सकता है.

(लेखक राजनैतिक विश्लेषक और वरिष्ठ पत्रकार हैं)

ज्योतिषाचार्य पंडित प्रियंका नारायणशंकर व्यास, कोतवाली बाजार, जबलपुर (म.प्र.)

आज जिनका जन्मदिन है

वर्ष के प्रारंभ में शिक्षा प्रतियोगिता में सफलता मिलेगी. आकस्मिक धन लाभ होगा. वर्ष के मध्य में व्यापार में लाभ होगा. शासन सत्ता का सुख मिलेगा. वर्ष के अन्त में शारीरिक कष्ट रहेगा.मित्रों से व्यर्थ का विवाद होगा. स्थानान्तरण का योग है. मानसिक तनाव में वृद्धि होगी.

मेघ और वृश्चिक राशि के व्यक्तियों को शारीरिक कष्ट होगा. वृष और तुला राशि के व्यक्तियों को शासन सत्ता का

सुख मिलेगा. मित्रों से व्यर्थ वाद विवाद होगा. कर्क राशि के व्यक्तियों को व्यक्तित्व का विकास होगा. मिथुन और कन्या राशि के व्यक्तियों को आकस्मिक धन लाभ होगा. धनु और मीन राशि के व्यक्तियों को मानसिक तनाव में वृद्धि होगी.स्थान परिवर्तन का योग है. सिंह राशि के व्यक्तियों को राजकीय सहयोग मिलेगा. मकर और कुंभ राशि के व्यक्तियों को नई योजनाओं में लाभ होगा.

सिंह- जो भी कार्य शुरू करेंगे, उसमें सफलता मिलेगी. अधूरी योजना को फिर से शुरू करेंगे. व्यर्थ के तनाव को टालें. पुन्य व्यक्ति की सलाह हितकारी रहेगी.

कन्या- बुजुर्गों के मार्गदर्शन से लाभ का योग है. पारिवारिक जीवन सुखमय रहेगा. व्यापार की योजना कारगर रहेगी. मानसिक तृल्ला बनी रहेगी.

तुला- प्रतिबन्धी परीक्षा में सफलता आसार हैं. विवादास्पद मामले सुलझ सकते हैं. आपकी बुद्धिमानी और सूझबूझ से विवाद का समाप्ा.

वृश्चिक- दूसरों के मामलों में दखल से बचें. अटके काम को पूरा करने की शिक्षा के क्षेत्र में सफलता प्राप्त होगी. नियमितता का ध्यान रखें.

आज जन्म शिशु का भविष्य

आज जन्म लिया बालक निडर, साहसी, महत्वाकांक्षी एवं आकर्षक व्यक्तित्व का होगा. बचपन में स्वास्थ्य नरम गरम रहेगा. अस्थिर बुद्धि का होने से उटपटांग बात करेगा. विद्या प्रारंभ में कम एवं बाद में अच्छी रहेगी. मित्रों की संख्या अधिक होगी. माता पिता का आदर करेगा.

उदयकालीन ग्रह स्थान

9	8	के.7 च.यु.	6	5
	10	श.	4	
11	12	रा.	2	3

पंचांग

रा.मि. 01 संवत् 2083 आषाढ शुक्ल नवमी गुरुवासरे दिन 8/39, विशाखा नक्षत्रे रात 3/52, शुभ योगे रात 10/26, कौलव करणे सू.उ. 5/20, सू.अ. 6/40, चन्द्रचार तुला रात 9/21 से वृश्चिक, शु.रा. 7, 9, 10, 1, 2, 5 अ.रा. 8, 11, 12, 3, 4, 6 शुभांक- 9, 2, 6.

व्यापार भविष्य

आषाढ शुक्ल नवमी को विशाखा नक्षत्र के प्रभाव से सोना, चांदी, के भाव तमें 30 से 40 रूपये मंदी होगी. धान्यों के भाव में अस्थिरता रहेगी. कपास, वस्त्र जुट, पाट, बारदाना, के भाव में मंदी होगी. भाषायांक 3441 है.

SUDOKU7458

3	9		1	4			2
1	2		6	3	5		
		5		8	7		9
	7		6	9			8
2	1		5			4	6
4		3	2		9		
9		8	4	5			
	6		9	5		2	4
8			1	7		6	3

नवभारत संपादक 7457

6	9	2	3	7	4	5	8	1
3	8	5	6	2	1	7	4	9
7	4	1	8	9	5	6	2	3
2	3	9	5	4	6	8	1	7
1	7	4	9	8	3	2	6	5
5	6	8	7	1	2	9	3	4
4	5	7	1	6	8	3	9	2
8	2	3	4	5	9	1	7	6
9	1	6	2	3	7	4	5	8